

[Shri Govindrao Adik]

went to the developed COUNTRIES, particularly, Europe and the United States of America. Japan invested in other Asian countries also like Thailand, Malaysia and China. Though these countries, Japan made inroads into the markets of the western countries. With our accent on exports, Japan was least interested in India. Even after liberalisation Japan continues to be reluctant India is still way down in Japanese priorities China sets the top priority as the Chinese have offered waiver of Corporate tax for two years. And our domestic market is not yet quite open. The Japanese investors are not interested in joint ventures which care for export business. Their main interest would be the domestic market in the investee countries. According to Merrill Lynch, one of the world's largest securities firms of the U.S., the foreign financial investors registering in India are facing several technical problems in the form of custodial services, in the areas of settlement, etc. The officials of this firm are reported to have said that if the Indian Government removed all the impediments in the way of foreign investment, there would be a significant increase in FFI's commitment. They further added that price-earnings ratio needed to be brought to international levels, and so far as the custodian problems are concerned, the Indian Government should streamline the business and adopt some of the changes taking place in other upcoming markets.

Sir high import tariffs inadequate protection of intellectual property rights and political instability are still considered as major hurdles to foreign investment in India, according to a survey conducted for the Indo-US Joint Business Council. On these findings of the survey, the Indian Government must take measures to inform the US businessmen of the

pace of reforms. And the non-Prime Minister, who is shortly visiting the United States, I am confident would explain the liberalisation process himself to the US investors during his forthcoming visit to that country. Changes should be made to make business more attractive, and there is a need to decrease Government-bureaucratic controls, in addition, increasing liberalisation efforts and tariff and duty reductions are also desirable changes. India also needs to demonstrate a stronger commitment to privatisation as part of its liberalisation policies to attract foreign investors.

So, in a nutshell these are some of the major problems, and also suggestions to make up the shortfall in investment by foreign financial investors. If this shortfall is made up, we shall be able to maintain and improve the industrial growth rates contemplated by the Government, and also the employment levels in our country. Thank you very much.

Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes and fulfilment of backlog in vacancies

श्री मोहनन्दर सिंह फल्याण (पंजाब) :
वाइस चेयरमैन साहब, आपका बहुत
शुक्रिया कि आपने मुझे वक्त दिया।

“आपने तार चलाया तो कोई बात
न थी,
हमने जन्म दिखाए तो बुरा
मान गए।”

बड़ी देर से जो हमारा शेड्यूल कास्ट
जिसको कह देते हैं, दलित बोलते हैं,
बड़े-बड़े नाम हमारे नाम पर जोड़े गए,
लेकिन इनको सुधारने के लिये बहुत कम
वक्त होता है, बहुत कम इस पर ध्यान
दिया जाता है। लेकिन एक बात यह कि
इनको इंसान भी समझा नहीं जाता था।
हमारे लोगों के साथ स्कूलों, कॉलेजों
और मन्दिरों में जाने की इजाजत नहीं

होती थी और बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन होता था। आजादी के बाद हमें कुछ रिलीफ मिली। एक ऐसा खुदा ने फरिस्ता भेजा जिसको महात्मा गांधी कहते हैं, उन्होंने यह लोगों के लिये एक अच्छा प्रचार किया कि ए हिन्दुस्तान के लोगों, यह लोगों से जो आप नफरत करते हैं, जो इन लोगों से आप दूर रहते हैं, मन्दिरों-मस्जिदों में जाने नहीं देते, तो ये भी उस परमात्मा के बन्दे हैं, ये हरिजन हैं। ये हरिजन जो लोग हैं, ये खुदा के ही पैदा किये हुए लोग हैं। लेकिन कुछ लोग महात्मा गांधी को बुरा-भला कह कर हरिजन लोगों को, जिन्होंने इतना बड़ा हमारे लिये काम किया, उन लोगों को यह भी बतलाया गया कि यह लोग जो टट्टी उठाते हैं या टट्टी का काम करते हैं, गन्दा उठाते हैं सिर पर, ये लोग भी हरिजन हैं। इन लोगों से नफरत नहीं करना चाहिये। महात्मा गांधी जी खुद अपनी टट्टी आप साफ करते थे और अपनी घर वाली को भी कहते थे कि यह टायलेट जो है, लैट्रिन जो है, उसको आप साफ करो। इसका सबूत यह 9 तारीख का "ट्रिव्यून" मेरे पास है, इसमें एक एडिटोरियल दिया हुआ है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। उन महात्मा गांधी ने हमारी झुग्गी-झोंपड़ियों में जाकर यह लोगों को दिखाना चाहा कि मैं उच्च जाति से हूँ, हमें उससे कोई नफरत नहीं। मुझे कोई ऐसी बीमारी नहीं लगती। हमें कोई ऐसा इनसे नफरत नहीं। कोई ऐसा किसी किस्म के उंची जाति वाले नीची जाति से मिलकर कोई आदमी को आदमी से डिफेंड, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। आओ हम इन क्षुभितियों में चलें और इनकी सेवा करें ताकि लोगों को यह पता चल जाए कि गरीबों की सेवा करने से एक अच्छा इंसान बनता है।

उन्होंने बड़ा हमारा काम किया और झुग्गी-झोंपड़ा को दूर करने के लिये यत्न किये। उसी तरह गुरु गोविन्द सिंह जी, जोकि दसवें बादशाह हुए हैं, उन्होंने भी लोगों के लिये यही एक उपदेश दिया था कि यह लोग भी हमारे में से हैं। हम सब को इनसे

प्यार करना चाहिये। इनके साथ रहना चाहिये। वह भी खुदा के बन्धे हैं। गुरु गोविन्द सिंह जी ने, जब पंच प्यार साक्षे थे, और उनमें छोटी जाति के लोग थे, उन सबको इकट्ठा किया। उनको अमृत छकाया और वह अमृत खुद बचा और लोगों को यही शिक्षा दी कि इन लोगों से नफरत नहीं करना चाहिये। उन्होंने तब कहा था कि, "रिगरेटें गुरु के बेटे" तो महोदय मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार ने कुछ काम किया है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी उस काम को चलने नहीं देती। पिछले साल सफाई कर्मचारियों के लिये एक बिल बनाया गया कि देश के जो लोग सिर पर गन्दगी उठाते हैं, वह उन्हें सिर पर उठाना नहीं चाहिये। जो गन्दगी का काम करने वाले लोग हैं, वे उस काम को छोड़ेंगे, हम उनको रिलीफ देंगे। उस बिल को बनाने की शुरुआत तो नहीं बतायी गयी, लेकिन बिल को समाप्त करने के लिये उसमें जगह दी गई है।

महोदय, इसके अलावा जो हमारा रिजर्वेशन है, उसके बारे में बड़ी चर्चा होती रही है कि जो हमारे शुडयूल्ड कास्ट के "ए" ग्रेड के लोग हैं और उनका जो साठे 22 परसेंट के हिसाब से पुराना रिजर्वेशन है, वह पूरा नहीं किया जा रहा है। हमेशा उसमें गैप होता है। "ए" ग्रेड में जो शुडयूल्ड कास्ट या शुडयूल्ड ट्राइब्स के हैं। मेरे हिसाब से पिछले तीन साल से उसके लिये हमारे 65 हजार आदमी ऐसे ही खाली पड़े हैं। जब आप 65 हजार आदमियों को उन जगहों पर लायेंगे तब जाकर यह गैप पूरा होगा। इसी तरह ग्रेड "बी" में भी 10 हजार का बकलॉग है। यह पोस्ट्स भी खाली पड़े हैं और 10 हजार लोगों को आप जगह देंगे तब वह बकलॉग पूरा होगा। फिर महोदय, ढाई हजार के लगभग प्रेज्युट्स हैं, जो कि अन-एम्प्लाइड हैं और 33 हजार के करीब पोस्ट-ग्रजुएट हैं, 8 हजार के करीब इंजिनियर हैं और ढाई हजार के करीब डॉक्टर घुम रहे हैं

और 21 हजार लोग ऐसे हैं जो इधर-उधर घूमते हैं। वे एम्प्लायमेंट आफिस में जाते हैं, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में नाम लिखाते हैं, लेकिन उनको कोई पूछनेवाला नहीं है। तो मेरी आपसे दरखास्त है कि जो बैंगलॉग हैं, इसे पहले भरा जाना चाहिये।

दूसरे महोदय जी, जो ग्रेड "ए" में आय.ए.एस. या आय.पी.एस. बन जाता है, उसमें यह होता है कि उनको आय.ए.एस. में नहीं रखते। उसके नम्बर कम होते हैं तो उसको अलाइड सर्विसेज में भेज देते हैं। इसलिये मेरी आपसे दरखास्त है कि अगर उसने आय.ए.एस. या आय.सी.एस. कैंडिडेट में क्लियर कर लिया है तो जो हमारा रिजर्वेशन है, कानून के मुताबिक उसको आय.ए.एस. में ही रखना चाहिये और अलाइड सर्विसेज में नहीं भजना चाहिये। उसको आय.ए.एस. में ही पोस्ट देना चाहिये। अगर वह आय.ए.एस. बना है या आय.पी.एस. बना है, तो ऐसा किया जाना चाहिये। यह मेरी एक दरखास्त है।

महोदय, मैं बैकलॉग के संबंध में एक बात और कहना चाहूंगा कि अगर इसी रफ्तार से हम पूरा करने जा रहे हैं, तो वह कई सालों में नहीं भरेगा। महोदय, पिछला बैकलॉग तो पूरा नहीं करते और अगर सौ पोस्ट्स आती हैं, तो उसको देखते हैं कि कितनी हैं... उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं और पिछला नहीं देखते, जबकि पिछला बैकलॉग पूरा करने करने के बाद आगे बढ़ना चाहिये। यह बैकलॉग नान-शेड्यूल्ड कास्ट के लिये भरा जाता है। हमारी जो पोस्ट्स होती हैं, उन पर दूसरे लोग नहीं आने चाहिये।

दूसरे एक सीट रिजर्व है, तो उस पर नान-शेड्यूल्ड कास्ट तो प्रोटेस्ट नहीं सकता है। इसलिये मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो हमारी पोस्ट्स रिजर्व हैं, उन पर दूसरे लोग नहीं मुताइयन करना चाहिये और ये पोस्ट्स उन्हीं कैंडिडेट्स के जरिये भरी जानी चाहिये। दूसरा जो प्राइवेट सैक्टर है, जिसकी यहाँ पर बात होती है, इस प्राइवेट सैक्टर में मिले हैं, शुगर मिल हैं, दूसरी इण्डस्ट्री हैं, उनमें हमारे रिजर्वेशन का कुछ नहीं। जन गवर्नमेंट इनको कर्जा देती है, इनको जमीन देती है, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की सुविलियत देती है, टेलीफोन आदि की सुविलियत देती है, तो इन फैक्टरियों में भी हमारे आदमी होने चाहिये। जब बैंड फैक्टरी को गवर्नमेंट लेती है, तो उस फैक्टरी में जब कि हमारा कोई भी आदमी नहीं होता, उसके लिये मेरा आग्रह है कि ऐसी फैक्टरी तब लेनी चाहिये, जब उसमें रिजर्वेशन पूरा हो।... (समय की घंटी) ...

इसी तरह से जो कालेज होते हैं या स्कूल होते हैं, उनमें भी रिजर्वेशन पूरा नहीं होता। जब गवर्नमेंट उनको एड देती है तो यह रिजर्वेशन तो वहाँ पुरा होना चाहिये। गवर्नमेंट जब किसी स्कूल या कालेज को टेकओवर करती है तो टेकओवर करने से पहले जो रिजर्वेशन कोटा है उसके अनुसार स्टाफ पूरा करने का काम होना चाहिये।

वाइस चैंसलर साहब, आपने घंटी बजाई, मैं जल्दी जल्दी अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। मेरा आग्रह है कि मिलों में रिजर्वेशन कोटा पूरा होना चाहिये। हमारे आनरेबल प्राइम-मिनिस्टर साहब ने प्राइम मिनिस्टर योजना में रूपया रखा है, तो उस व्यक्ति को देना है, जो अनएम्पलाएड है और यह एक करोड़ लोगों को देना है। इसमें एक एक लाख रूपया हर उस व्यक्ति को मिलेगा, जिस व्यक्ति के पास रोजगार नहीं। अगर वह ट्रेड नहीं है, आई.टी.आई. सी.टी.आई. में जाकर उसने ट्रेनिंग नहीं की, तो उनको ट्रेनिंग देने के लिये भी एड दी जायेगी। जब इस योजना में प्राइम-मिनिस्टर साहब ने 22.5 फीसदी

शेड्यूल्ड कास्ट के लिये कोटा रिजर्व करके रखा है तो यह जो अदारे है, इनमें भी हमारा कोटा रिजर्व होना चाहिये। कई कारपोरेशन हैं, वहाँ पर हमारा कोई आदमी एम० डी० नहीं होता। उसमें दूसरे लोग जा होते हैं, वह फायदा उठाते हैं। इसलिये मेरी आपसे दरखास्त है कि इस ओर भी ध्यान जाना चाहिये।

उपसभाध्यक्ष (श्री सतीश अग्रवाल) : मोहिन्दर सिंह जी, बहुत महत्वपूर्ण विषय है और जो आप बातें रख रहे हैं, बहुत ही श्रेष्ठ और सुन्दर हैं।

श्री मोहिन्दर सिंह कल्याण : सर, दो मिनट से आगे नहीं जाऊंगा।

उपसभाध्यक्ष (श्री सतीश अग्रवाल) : मैं तो दे दूंगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन दस मिनट हो गए हैं। आपका काफी समय हो गया है। विषय तो ऐसा है जिस पर एक घंटा बोल सकते हैं। मुझे आपकी तैयारी से लगता है कि आप एक घंटे के मूड में हैं, लेकिन मैं इतना समय दे नहीं सकता आपको क्योंकि समय का अभाव है। अभी काफी मैम्बर, आपका तो नंबर छठा आया है, मेरे पास लिस्ट में 23 नाम हैं।

श्री मोहिन्दर सिंह कल्याण : आप वक्त देने को तैयार नहीं। हमारा काम आगे कैसे बढ़ेगा, अगर वक्त नहीं मिलता? कुछ कहने की बात नहीं, मैंने शुरू ही यहाँ से किया कि आप वक्त ही नहीं देंगे। आप तो सुनने के लिए तैयार नहीं। दो दो घंटे भी लोग बोलते हैं। कभी किसी ने शेड्यूल्ड कास्ट का मसला उठाया? हम जब मसला देते हैं और बोलते हैं तो आप बुरा मान जाते हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्री सतीश अग्रवाल) : नहीं, नहीं यह आप मत सोचिए।

श्री मोहिन्दर सिंह कल्याण : यही तो गलत है। आप रिजर्वेशन के लिहाज से भी हमें अपना वक्त दे दें। अगर नहीं देते तो मैं बैठ जाता हूँ।

उपसभाध्यक्ष (श्री सतीश अग्रवाल) : नहीं, नहीं। देखिए, आप ऐसे नाराज मत

होइए। अगर मुझे यह पता होता कि आप इतना ज्यादा समय लेंगे तो मैं सबके बाद आपको समय दे देता।

श्री मोहिन्दर सिंह कल्याण : आप जो हुकूम करें, अगर आप कहें तो मैं एकदम नीचे बैठ जाता हूँ।

उपसभाध्यक्ष (श्री सतीश अग्रवाल) : नहीं, आप बोलिए। जल्दी खतम कीजिए।

श्री मोहिन्दर सिंह कल्याण : सर, हमारी आपसे यह दरखास्त है। सुप्रीमकोर्ट और हाईकोर्ट में हमारा कोई नुमायदा नहीं है। हमारे लोगों का ऐसा है कि जब हाईकोर्ट में जज बनने के लिए जाता है तो उसके खिलाफ दरखास्तें दे दी जाती हैं और उसकी इन्क्वायरी शुरू हो जाती है। उसके बाद कोई और आदमी लगा दिया जाता है। वह आगे बढ़ता है। अगर इन्क्वायरी ही खतम नहीं होती। तो ऐसा नहीं होना चाहिए बल्कि जब उनका नाम आ जाए तो उनको लगा देना चाहिए और इन्क्वायरी होती रहे। अगर वह इन्क्वायरी में फसता है तो बाद में डिमिशन हो, लेकिन जो उसकी जगह है वह उसे मिलनी चाहिए।

हमारे हिन्दुस्तान में चीफ सेक्टरों हमारे बहुत कम हैं, कहीं कहीं सेक्टरों लगे हैं। मेरा ख्याल है कि एक दो ही जगह होंगी पूरे हिन्दुस्तान में, जहाँ हमारा कोई चीफ सेक्टरों होगा। इस तरफ भी हमें ध्यान देना चाहिए। जो हमारे आई. ए. एस. आफीसर हैं, उनको भी कहीं कोई अच्छी जगह नहीं दी गई। हमारे आदमी को कोई डिस्पेंच पर लगा दिया है, कोई प्रिंटिंग स्टेशनर पर लगा दिया है, कोई कहीं ऐसी जगह पर लगा दिया है और ऐसे ऐसे उन लोगों को जलील किया जाता है। तो इनके लिए भी गवर्नमेंट को चाहिए कि उनको भी कुछ अच्छी पोस्टें दें।

हम इस देश के वासी हैं। जब भी पंजाब में, हिन्दुस्तान में कभी ऐसी बात हुई है तो हमारे लोगों ने सबसे आगे बढ़कर कुर्बानी दी है। जब चीन और पाकिस्तान की लड़ाई लड़ी गई तो हमारे लोगों ने सबसे आगे होकर कुर्बानी दी है। हम देश को बचाने के लिए

[श्री मोहिन्दर सिंह कल्याण]

जान दे रहे हैं। हम देश की एकता चाहते हैं। हम देश को अलग अलग नहीं होने देना चाहते। हम देश के साथ जुड़कर काम करना चाहते हैं।

हमारी एक यह भी दरखास्त है, जो हमारे बच्चे हैं, उनको जो स्टैंडिंग आप देते हैं, वह बहुत ही कम है। आप देखिए, आपने 72 करोड़ रुपया 20 लाख बच्चों को देना है। अगर आपके जमाने में यह देखा जाए तो एक बच्चे को एक रुपया डेली आता है, अगर यह पानी का, स्कूल पढ़ने जाए और एक पानी का गिलास पीए तो उसके बाद उसको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए मेरी आपसे दरखास्त है कि इस स्कॉलरशिप में बढ़ावा होना चाहिए। जिस आदमी की 2,000 से अधिक तनखाह है, वह उसका लाभ नहीं उठा सकता है। दूसरी बात यह है कि दो बच्चों से ज्यादा उनको यह स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। तो मेरी आपसे दरखास्त है कि जो हमारा काम है, हमारा काम यह है कि जो हमारे विधान में हमें रियायतें दी गई हैं, हम और नहीं मांगते, वे शैड्यूल्ड कास्ट को पूरी मिलनी चाहिए। इसलिए यह मेरी आपसे दरखास्त है, ... (समय की घंटी) ... मेहरबानी है आपकी वक्त तो और भी लेना चाहता था, वक्त के लिए भी दरखास्त करनी पड़ती है, बोलने के लिए भी दरखास्त करनी पड़ती है।

उपसमाध्यक्ष (श्री सतीश अग्रवाल) : अगली बार जब शैड्यूल्ड कास्ट, शैड्यूल्ड ट्राइब्स कमिशन की रिपोर्ट पर बहस होगी तो मैं आपको 10-15 मिनट ज्यादा दूंगा, अगर मैं हुमा तो।

श्री मोहिन्दर सिंह कल्याण : खुदा करें आप इस चेयर पर हों। धन्यवाद।

उपसमाध्यक्ष (श्री सतीश अग्रवाल) : अवश्य दूंगा।

Need to set up telegraph offices in Rayagada and Koraput Districts in Orissa

SHRIMATI ILA PANDA (Orissa): Mr, Vice-Chairman, Sir, through you, I would like to draw the attention of the hon. Minister of Communications

to a genuine and long-standing demand of the people of the most under developed and economically, educationally and socially backward tribal areas of Rayagada and Koraput, in Orissa.

Sir, no amount of financial help in the form of bank loans under the various poverty-alleviation schemes, is going to improve the poor the condition of the people in these areas. What is required is the development of the infrastructural facilities there. Infrastructural facilities like railway, road, communications, etc., should be set up in these areas. But unfortunately, the tribal districts of Orissa are in a state of neglect due to the callousness on the part of the Central Government.

In the year 1990, two telegraph offices were sanctioned by the Central Government to be set up in these areas. Four years have passed since the decision was announced. But I am very sorry to say that nothing has been done, so far, to implement this decision. This is a basic need of the people. Communication is a basic need of the people. There cannot be a greater example of the neglect of the tribal areas than this.

Therefore, I implore the Central Government not to go back on their promise after announcing various developmental measures for the backward and tribal areas. What is required is the will to translate this decision into reality. Please do not Join

hands with the cruel Nature which often inflicts suffering in the form of chronic drought in the tribal districts of Orissa.

I would once again urge upon the hon. Minister of Communications to start the work of setting up of these offices in these areas immediately.

Thank you